(c) and (d). Do not arise. The Soviet experts have given preliminary proposals for setting up of plants for manufacturing prefabricated canal structures. These proposals are being considered in consultation with the State Government.

T.V. Team sent to Film Thar Desert

1543. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether a T.V. team of Delhi Doordarshan was sent in October, 1979 to film the first-ever Thar Desert expedition organised by a Mountaineering Association of Delhi;

(b) if so, the basis on which the team was selec edfor this important event;

(c) the total expenditure incurred on the team includ ng the cost of the raw film used;

(d) whether the film has been telecast since then; and

(e) if so, when and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI VASANT SATHE): (a) Yes, Sir.

(b) Members of the team were selecced on the basis of their suitability, area of interest, capacity to undertake the assignment, etc.

(c) A total expenditure of Rs, 6 807/] was incurred.

(d) and (e). A small portion of the film was utilised in Doordarshan' News Bu letins on 19-10-1979 The rest of it is being u ed for produ ction of two T.V. documenta ies.

जबलपुर में सूक्ष्म तरंग टावर की स्थापना

1544. श्री मुंडेर शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर को टेलीविजन रेंज के अन्तर्गत लाने के लिए जबलपुर में या उसके निकट किसी अन्य स्थान पर सूक्ष्म तरंग "टावर" स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) वह किस स्थान पर तथा कब स्थापित की जायेगी तथा जबलपुर में टेलीविजन सेवा कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). डाक व तार विभागा की दिल्ली और नागपुर को जोड़ने की योजना के एक अंग के रूप में नागपुर और जबलपुर के बीच एक सूक्ष्म तरंग संपर्क कार्य कर रहा है । तथापि, इसमें फिलहाल दूरदर्शन के संकेतों को प्रक्षेपित करने की क्षमता नहीं है ।

वित्तीय संसाधनों की कमी और दूरदर्शन के विस्तार को कम प्राथमिकता देने के कारण, चालू योजना अवधि (1978—83) के दौरान जबलपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Setting up of High Court Benches at Aurangabad and Poona

1545. SHRI V. N. GADGIL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received a re ommendation from the Government of Maharashtra that a Bench of the High Court should be established at Aurangabad and Poona; and

(b) if so, whether Government have accepted the recommendat on?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

सरकारी बिजली घरों के निर्माण-कार्य का निजी क्षेत्र को दिया जाना

1546. श्री हरि कृष्ण शास्त्री : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी बिजली घरों के निर्माण-कार्य को निजी क्षेत्र को दिए जाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : जी नहीं । सरकारी बिजली घरों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र को दिए जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । बिजली घरों के वास्तविक निर्माण के बारे में वर्तमान प्रयासों के अनुसार या तो विभागीय निर्माण संगठन को निर्माण कार्य सौंप दिया जाता है या निजी ठेकेदारों से या सरकारी क्षेत्र के निर्माण निगमों से इनका निर्माण कराया जाता है ।

Development and completion of Rajasthan Canal

1547. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that world Food Programme has evinced interest and assured cooperation for the development and completion of the Rajasthan Canal Area and the Canal system;

(b) if so, the nature of assistance that has been offered by WFP in this connection;

(c) what would be the total contribution of the WFP for the development of the canal system and for the adjoining areas separately and how many additional worker can be engaged under this scheme; and

(d) whether the offer has been accepted, if so, its terms and conditions and by what time it will be implemented ?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A B A GHANI KHAN CHAUDHURI): (a) The World Food Programme (WFP) has been providing food aid for the labourers working on the Rajasthan Canal Project since September, 1968.

(b) The WFP has offered commodities such as wheat, edible oil, dried skim milk, pulses and beans. These commodities are sold to the labourers at concessional prices.

(c) The total contribution of WFP for the Rajasthan Canal Project would be about 21 million dollars (Rs. 16 8 crores) and is estimated to generate employment of about 98 million man days.

(d) The offer has been accepted by the Government of India. According to the terms and conditions, the WFP supplies commodities and these are sold at about half the prevailing market prices to the labourers working on the Rajasthan Canal. The amount realised from the sale of commodities supplied by WFP is utilised for the development schemes relating to Agriculture, Soil Conservation Animal Husbandry, Forest Nurseries and Plantations. Besides, during the current phase of development, the amount will be utilised for the provision of medical and health facilities, safe drinking water supply, schools, provision of veterinary facilities for the development of animal husbandry etc. According to the present arrangement, the WFP assistance is to be continued till 1983.

कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य और उपलब्धता

1548. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य और उसकी उपलब्धता की स्थिति असंतोषजनक रही है ?

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी): राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन 1973-74 के 78 मिलियन टन से बढ़कर 1976-77 में 101 मिलियन टन हो गया और इसके बाद वह बढ़कर 1978-79 में 102 मिलियन टन हुआ । खान मुहाना स्टाक भी अप्रैल, 1974 के 6.43 मिलियन टन के मुकाबले अप्रैल, 1979 में बढ़कर 14.34 मिलियन टन हो गया । कोयले की मांग 1976-77 तक कुल मिलाकर पूरी ही की जाती रही । कुल विशेष किस्म के कोयले के उत्पादन में कमी और रेल परिवहन की उपलब्धि में कमी के कारण 1977-78 और 1978-79 में उपभोक्ताओं को कोयला कम मिला ।

जो खान मुहाना कीमत 1-4-1975 में नियत की गई थी वह 17-7-1979 तक वही बनी रही । इस तारीख को इसमें संशोधन किया गया था । इसमें संशोधन आवश्यक हो जाने के कारण थे—मजदूरी में वृद्धि और उत्पादन के साधनों आदि की लागत बढ़ जाना ।